रही है। देश मे यूरिया की कमी है। यह मंत्री जी ने स्वीकार किया है। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि यूरिया जिस रॉ-मेटिरियल से बनता है— गैस से या नाफ्था से- क्या देश में उसकी कमी है? यदि कमी है तो उसे पूरा करने के लिए आप क्या उपाय कर रहे हैं? क्या आपने गैस के लिए किसी देश से समझौता किया है जिससे कि आप गैस आधारित यूरिया का और अधिक उत्पादन करके देश में जो कमी है, उसकी भरपाई कर सकें?

श्री शीश राम ओला: सभापति महोदय, गैस का हमारे मंत्रालय से कोई संबंध नहीं है, पेट्रोलियम मिनिस्ट्री का उससे संबंध है। पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ही हमको गैस आवंटित करती है और यहां से गैस और नैफ्था आने के बाद हमको उसका एलॉटमेंट होता है। जो स्थिति है वह मैंने आपके समक्ष रखी है, हर साल के आंकड़े मैंने आपके सामने रखे हैं। यहां 5 लाख या 6 लाख टन यूरिया की कमी थी। मैंने स्पष्ट तौर से निवेदन किया है कि इन 3-4 यूनिटों में उत्पादन में कमी आई, जिसकी वजह से हमारे यहां यूरिया उत्पादन के लक्ष्य में कमी हो गई। इस वर्ष का हमारा उत्पादन का लक्ष्य 1997-98 का 175 लाख टन है। हम कोशिश कर रहे हैं कि आयात कम हो और देश में यूरिया का उत्पादन अधिक हो। हम इसके लिए प्रयत्नशील है। हमें उम्मीद है कि निश्चित तौर से यूरिया का उत्पादन राष्ट्र में बढ़ेगा और आयात कम होता चला जाएगा।

श्री नरेश यादव: सभापति महोदय, मंत्री जी ने अपने जवाब में कहा है कि पहले 6 महीनों में 5.1 परसेंट यूरिया की कमी हुई है। अब मंत्री जी बार-बार कबूल कर रहे हैं कि यूरिया की कोई कमी नहीं है। कहीं न कहीं अंतर तो है। या तो जवाब गलत आया है या मंत्री जी सही बोल रहे हैं। अंतर कहां है? मंत्री जी कबूल कर रहे हैं कि यूरिया की कमी नहीं है और जवाब में दिखाया गया है कि यूरिया की कमी है।

श्री शीश राम ओला: मेरे ख्याल से समझ में फर्क है। ये शायद मुझे समझ नहीं पा रहे हैं। मैं स्पष्ट निवेदन कर रहा हूं कि 3 यूनिटों में प्रोडक्शन ठीक से न होने की वजह से कमी आई। इंडोगल्फ 2 लाख 50 हजार टन, आर.सी.एफ. एक लाख, 77 हजार टन, एन.एफ.एल. एक लाख, 66 हजार टन, कुल 5 लाख 93 हजार टन की कमी आई। यह जो कमी है, इसका कारण मैंने स्पष्ट कर दिया है। अब इसके बाद उसी बात को कितनी बार दोहराऊंगा? हम यह चाहते हैं कि यूरिया का उत्पादन राष्ट्र में अधिक हो। इसके लिए 6 और परियोजनाएं प्रोडक्शन में आने वाली हैं। पहले हम जो यूरिया बाहर से लाते थे, अब उससे कहीं कम यूरिया ला रहे हैं और आहिस्ता-आहिस्ता इसमें और कमी आएगी और हमारे यहां उत्पादन अधिक होगा, यह हम चाहते हैं।

श्री जर्नादन यादव: सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि देश में यूरिया की कितनी आवश्यकता है और आपने उत्पादन कितना किया है? आज यूरिया का देश में बहुत अभाव है और उसको आप हिंदुस्तान के उत्पादन से पूरा नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए आप विदेशों से यूरिया मंगा रहे हैं। इस देश में यूरिया की आवश्यकता कितनी है और उत्पादन कितना कर रहे हैं और विदेशों से कितना मंगा रहे हैं, यह मैं जानना चाहता हूं।

श्री दीपांकर मुखर्जी: देश में 211 लाख टन की जरूरत है। 1997-98 में और मंत्री बोल रहे हैं कि 175 लाख टन का उत्पादन करेंगे। बाकी इंपोर्ट करेंगे क्या ...**(व्यवधान)**

Two hundred lakh tonnes of urea is required in 1997-98. ...*(Interruptions)*

SHRI TRILOKI NATH CHATURVEDI: Sir, the CPI Member has got now a CPM Deputy Minister or Minister of State. It is good. There is a good harmony in the House.

SHRI DIPANKAR MUKHERJEE: I am asking the Minister to reply.

श्री जर्नादन यादव: मंत्री जी जवाब दीजिए।

श्री शीश राम ओला: मैं चैलेंज करता हूं कि मेरी जानकारी आंकड़ों के हिसाब से तथ्यपूर्ण है। सन् 1993-94 में आयात हुआ था 27.85 लाख टन, 1994-95 में आयात हुआ था 28.70 लाख टन और 1995-96 में आयात हुआ था 37.82 लाख टन।

SHRI DIPANKAR MUKHERJEE: Sir, we are being misled. There is a gap of 13 lakh tonnes. ...*(Interruptions)*

MR. CHAIRMAN: The Question Hour is over.

WRITTEN ANSWERS TO STARRED QUESTIONS

"Study on Environmental Threat by Emission of Greenhouse Gases"

*582. DR. MOHAN BABU: Will the Minister of ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state:

(a) whether Government have made any in-depth study of the environmental threat caused by emission of greenhouse gases in India which is supposed to be the sixth largest producer of carbon dioxide emissions;

(b) if so, the details of the study made and the agency which had undertaken the study; and

(c) the steps being contemplated to combat the growing menace?

THE MINISTER OF ENVIRONMENT AND FORESTS (PROF. SAIFUDDIN SOZ): (a) Under a Technical Assistance Project from the Asian Development Bank the Government has completed in 1994 a study entitled "CLIMATE CHANGE IN ASIA: India Country Report" wherein analysis of vulnerability to climatic and whether related events, the potential impacts of Climate Change and preliminary estimates of national greenhouse gas emissions have been worked out. The Government is not aware of any study in support of the statement that India is the sixth largest producer of carbon dioxide emissions. On the other hand, according to data available from some studies, the annual net emissions of all greenhouse gases in India, as percentage of global emissions, is of the order of 0.013% only which is not significant as compared to a number of developed and developing countries.

(b) In this study, scientists and experts from various research institutions and universities such as National Physical Laboratory, New Delhi; India Agricultural Research Institute, New Delhi; Indian Institute of Science, Bangalore; Jawaharlal Nehru University, New Delhi; Tata Energy Research Institute, New Delhi; Indira Gandhi Institute of Developmental Research Bombay; Management Services Group, New Delhi had participated. The study has shown that India's past and present carbon diosxide emissions are not significant. Further, the methane emissions from paddy fields in India is in the range of 2.5 — 6.0 terra grams per year as against 37.8 terra grams per year projected in other studies from the developed countries.

(c) The Government is aware of the problem. India is a Party to the United Nations Framework Convention on Climate Change whose objective is to achieve stabilization of greenhouse gas concentrations in the atmosphere at a level which would not harm the global climate system. As per the existing obligations under this treaty, India is not required to adopt any national greenhouse gas reduction targets. Notwithstanding this, several measures have been adopted to promote efficient utilisation of fossil fuels, use of renewable energy technologies, abatement of pollution, conservation of forests etc. Besides, a framework of legislative and policy measures are in place which would help in minimizing the causes of climate change.

"राजाजी राष्ट्रीय उद्यान में वन्य जीवों के आवागमन में बाधा पड़ना"

*584. **श्री सूर्यभान पाटील वहाडणे:** क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि.

(क) क्या राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, देहारादून के वन्य जीवों, विशेषकर हाथियों के उन्मुक्त आवागमन में गंगा नदी के दोनों और, मानवीय कारणों से बाधा पड़ रही है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे मानवीय कारणों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन बाधाओं के कारण हाथियों की जनसंख्या पर प्रभाव पड़ रहा है;

(घ) क्या इस राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र में वन गूजरों,